

Member has any information, he can send it to the Minister so that he would be able to pursue the matter.

THE PRIME MINISTER (SHRI P.V. NARASIMHA RAO) : We do not know where she is.

MR. CHAIRMAN : The University does not know where she had gone. If the hon. Member has any information, he can send to the Minister.

*124. [The questioner (Shri Ram Singh Rathaur) was absent. For answer, vide Col.infra]

Opening of Skies to Foreign Airlines

*125. SHRI VIRENDRA KATARIA Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report captioned "India to open skies to foreign airlines" which appeared in the Times of India dated the 12th February, 1994; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) Yes, Sir.

(b) Government do not propose to allow foreign airlines to operate to India without conditions of reciprocity. Entitlements for flight operations will continue to be settled with Governments of other countries, under the prevailing bilateral system.

श्री वीरेन्द्र कटारिया : जनाब चेंबरमैन साहब क्या वजीरे शहरी हवाबाजी बतायेंगे कि कुछ रोज पहले केबीनेट सेक्रेटरी साहब ने कुछ एयर लाइंस की, इंटरनेशनल एयर-लाइंस की एक मीटिंग सदारत की थी जिसमें ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, लुफ्थांजा, सिंगापुर एयर लाइंस, गल्फ एयर और एयर इंडिया के नुमाइंदे शामिल थे। मैं आनरेबल वजीर साहब से जानना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में क्या कोई फार्मल फैसले हुए हैं और अगर फार्मल फैसल हुए हैं तो उनकी क्या डिटेल है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : सभापति महोदय, जहां तक मीटिंग का संबंध है, मीटिंग हुई थी लेकिन वह मीटिंग उसमें जो न्युज आइटम आई थी यह कोई कतई फैसला करने के लिए नहीं की गई थी ट्रेड, इंडस्ट्री और बाकी जगहों से जो साल भर से लोगों के मशविरें आ रहे थे, लोगों की सलाह आ रही थी, वह तमाम एक पेपर में कम्पाइल किये गये थे और उस पर चर्चा हुई थी। तो वह कोई सरकार की तरफ से ऐसा पेपर नहीं बनाया गया था कि जिस पर कोई फैसला लेना था या निर्णय लेना था उसको जितने लोगों ने सलाह दी थी साल भर में उस को एक पेपर में कम्पाइल करने के लिए, पेपर डिसकशन करने के लिए पेपर बना हुआ था, उस पर चर्चा हुई थी। लेकिन इस समय का वक्त देते हुए क्यों कि बहुत सारे पेपरों में उस की चर्चा आई है तो मेरे ख्याल में जो लोगों के मन में उस के लिए आशंकाएं और शक पैदा हुआ है उस के लिए उस शक को मैं खत्म करना चाहता हूँ।

There has been a lot of speculation about the "Open Sky" policy. I have already clarified it on the floor of the Lok Sabha on the 23rd of February, 1994 and would like to reiterate the clarification so as to set the speculations at rest. By repealing the Air Corporations Act, we have opened the Indian sky for operation of scheduled flights by domestic airlines only and not foreign airlines. Government has no intention of making our sky free for all.

श्री वीरेन्द्र कटारिया : चेंबरमैन साहब, मैं वजीरे शहरी हवाबाजी और टूरिज्म से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में जो रेस्ट्रिक्टेड परमिट सिस्टम है क्योंकि उस एरिया में बहुत सी इनसर्जेंसी है और यह मुल्क के इन्टररेस्ट में नहीं है कि उसको सब लोगों के लिए खुला छोड़ दिया जाए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की क्या कोई ऐसी पालिसी है कि इस परमिट को खत्म करके वहां पर फोरिन टूरिस्ट जाएं

टूरिज्म की बढ़ावा देने के नाम पे और इससे हमारे देश की सलामती पर कोई खतरा हो ऐसी कोई प्रपोजल इनके जेरे गौर है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : सर, यह तो होम मिनिस्ट्री करती है, यह टूरिज्म मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन नहीं करती है। जहां-जहां होम मिनिस्ट्री को वह लगता है कि जहां कोई प्रब्लम नहीं है वह एरिया हर साल टूरिस्ट के लिए खोल देते हैं।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे पास 747-400 नाम के जहाजों का कितना फ्लीट है और उसके एक जहाज की खरीद पर कितना खर्च आता है और "ब" पार्ट कि क्या... (व्यवधान)...

SHRI SURESH KALAMADI : Not related to the question.

श्री सोमपाल : आप एक मिनट सुनिए तो सही, वह बाहर वालों को खोलने की बात कर रहे हैं, हमारे पास ट्रैफिक नहीं है यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए पूछना चाह रहा हूं। क्या यह बात सही है उसका पूरा फ्लीट हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से कि हमारे पास ट्रेड पायलट्स पर्याप्त संख्या नहीं है। यदि ऐसी बात है तो बिना पायलट्स का इंतजाम किए सरकार ने वे जहाज क्यों खरीदे और कितने ऐसे जहाज हमारे पास अनुपयुक्त पड़े हैं और उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : सर, पहले तो यह सवाल इससे सम्बद्ध नहीं है पूरी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो हम इस क्वेश्चन में डिसकस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य जी ने कहा है कि हमारे जहाजों में पायलट्स की कमी है, उसमें कोई शक नहीं है कि नए जहाज जो लाए गए उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी और वह ट्रेनिंग अभी भी चल रही

है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में हम उसका कुल यूटिलाइजेशन करेंगे।

श्री सोमपाल : पर आपने संख्या नहीं बताई और खर्च नहीं बताया और कितने अनुपयुक्त पड़े हैं, यह नहीं बताया ?

MR. CHAIRMAN : Please. First of all the question is not relevant.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं शहरी हवाबाज और सैर-सपाटा वी जी से पूछना चाहूंगा... (व्यवधान)... एक माननीय सदस्य। यह पार्लियामेंटरी है ?

श्री एस० एस० अहलुवालिया : यह पार्लियामेंटरी है, अनपार्लियामेंटरी नहीं है।... (व्यवधान) सर, पंजाबी में यही कहते हैं हवाबाज और सैर-सपाटा मंत्री।... (व्यवधान)

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यहां पर प्राइवेट एयरलाइंस खोलने के लिए अगर नान रेजीडेंट इंडियन्स फारेन एयरलाइंस के साथ में कोई एलायंस करके, कोई एग्रीमेंट करके, परमिशन चाहे तो क्या उनको देंगे ? ऐसा जानने में आया है कि कुछ एप्लीकेशन्स आप के पास पेन्डिंग पड़ी है जिनमें झाई लाइसेंस या बेट लाइसेंस जो भी है वे इश्यू किये गये हैं। तो कितने किये गए हैं और कितने पेन्डिंग है यह बताने की कृपा करें।

श्री गुलाम नबी आजाद : सर, मैं हमारे ज्यादा बोलने वाले एम० पी० साहब से गुजारिश करूंगा कि इस तरह से जहां तक एन०आर०आईज० का संबंध है उनके लिए तो कभी भी छूट है। कोई भी एन०आर०आई० उसका परमिट ले सकता है। लेकिन फारेन इक्विटी अभी तक एक ही केस में एप्रुव हुई है और वह है 40 परसेंट उससे ज्यादा नहीं। कितने केसेज पेन्डिंग है, उसके लिए अभी जानकारी नहीं है क्योंकि वे तो एप्लाई करते हैं डाइरेक्टर जनरल, सिविल को। कम से कम मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है।

SHRI SANJAY DALMIA : The Government is allowing foreign companies to set up joint ventures in fields like Coca Co I would like to know why the Government does not allow joint ventures of the Indian companies along with the foreign companies to operate the airlines in India.

SHRI GHULAM NABI AZAD : I have said that as far as foreign equity is concerned, one person has applied so far and we have given permission to the extent of 40 per cent equity participation of a foreigner.

SHRI SANJAY DALMIA : That was about the NRIs. My question is about the Indian companies joining hands with foreign companies.

श्री गुलाम नबी आजाद : इंडियन्स के लिए तो बिल्कुल खुला ही खुला है। उसके लिए तो कोई प्रब्लिम ही नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : इनका सवाल कुछ और है।

SHRI JOHN F. FERNANDES : After repealing the Air Corporation Act, we do not have any statutory body at the moment with a statutory weapon and control. On the contrary we have more airlines. There are fifteen airlines and one domestic carrier, the Indian Airlines. The authority is handicapped because it is exercised by the International Airports Authority the National Airport Authority and the DGCA. In the absence of any statutory central command and control. I would like to know whether he would see that an Air Transport Board is incorporated so as to control all these airlines.

SHRI GHULAM NABI AZAD : After the repeal of the Act, we have already issued some guidelines and we have also taken the private airlines into confidence. We had a long meeting with them. On the basis of the consensus on the points which were of mutual interest, they have been incorporated in those guidelines.

We have also said that if at any point of time these guidelines are not adhered to, we would have some quasi-judiciary body to regulate the airlines. But it will be as and when required.

MR. CHAIRMAN : Q. No. 126.

Prices of Cephalixin—Based Formulation

***126. SHRI ANANT RAM JAISWAL† :**
SHRIMATI SATYA BAHIN :

Will the MINISTER OF CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state :

(a) what are the reasons of wide disparities in the prices of Cephalixin-based formulations like Alcepin, Alsporin, Nufex, Phexin Sepexin, Sporidex, etc.;

(b) what are the market prices in each case and what is the approved price;

(c) whether it is a fact that overcharging or manipulation of costs at the level of DPRC or its sub-committee is responsible for such a state of affairs; and

(d) what action Government propose to take to remove these anomalies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO) :

(a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There are no disparities in the approved prices of these Cephalixin based formulations.

(b) To the extent information is available, the market price of Cephalixin based formulations are in accordance with their approved Prices.

(c) and (d) Do not arise.

श्री अनन्त राम जायसवाल : सभापति जी क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीफेलेक्सिन और उस पर आधारित वह दवाएं जो कि सवाल के "ए" पार्ट में दे दी गयी है, वह ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत आती हैं ? अगर हाँ, तो क्या सरकार ने उनके दाम घोषित किए हैं अलग-अलग दवाओं के ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : सभापति जी, 1993 के दिसम्बर महीने से इस पर मूल्य नियंत्रण लागू किया

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Anant Ram Jaiswal.